Ved International Journal of Arts, Commerce and Technology (VIJACT)
© VIJACT |Vol.2, Issue2, Feb 2026, pp. 58-64 | ISSN: 3139-1656 (Online)
DOI: https://doi.org/10.65785/vijact.v2i2.18
Available online at: https://vijact.com/

ग्रामीण पर्यावरण में नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण

अवनीश कुमार [1] एवं डॉ० हरिओम गुप्ता [2]

[1] शोध छात्र, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
[2]एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

Article Info

Article history:
Received Feb 16, 2026
Accepted Feb 27, 2026
Published Feb 28, 2026

Keywords:
नगरीकरण
ग्रामीण परिवर्तन
सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण
पलायन
गोरखपुर

ABSTRACT

भारत में नगरीकरण अब केवल महानगरों तक सीमित परिघटना नहीं रह गई, बल्कि यह ग्रामीण अंचल की सामाजिक-आर्थिक बुनावट को गहराई से बदल रही है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य गोरखपुर जिले के संदर्भ में नगरीकरण से उपजे ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना है। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, जिसमें जनगणना 2011, जनसंख्या प्रक्षेपण एवं शासकीय प्रतिवेदनों के आँकड़ों का प्रतिशत, वृद्धि-दर एवं तुलनात्मक विधि से परीक्षण किया गया। परिकल्पना यह रही कि नगरीकरण के साथ ग्रामीण जनसंख्या का सापेक्ष अनुपात घट रहा है तथा कृषि पर निर्भरता कम होकर गैर-कृषि रोज़गार, साक्षरता एवं पलायन बढ़ रहा है। परिणाम दर्शाते हैं कि जिले की 81.17 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के बावजूद नगरीय हिस्सा तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्रामीण-नगरीय साक्षरता अंतराल बना हुआ है, और रोज़गार-ढाँचा कृषि से सेवा-निर्माण क्षेत्र की ओर खिसक रहा है। निष्कर्ष यह है कि नगरीकरण अवसर एवं असमानता, दोनों को साथ लाता है, अतः संतुलित ग्राम-नगर नियोजन आवश्यक है।

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Corresponding Author:
अवनीश कुमार
Email: avaneesh16aryan@gmail.com

1. परिचय

नगरीकरण किसी भी विकासशील समाज की सबसे निर्णायक संरचनात्मक प्रक्रियाओं में से एक है। भारत में यह प्रक्रिया इक्कीसवीं सदी में अप्रत्याशित गति से बढ़ी है। भगत (2011) रेखांकित करते हैं कि जनगणना 2011 में पहली बार स्वतंत्रता के बाद नगरीय जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि ग्रामीण वृद्धि से अधिक रही, जिसने पूर्व के दशकों की मंद प्रवृत्ति को पलट दिया। यह परिवर्तन केवल जनसंख्यात्मक नहीं है; इसके साथ रोज़गार, भूमि-उपयोग, पारिवारिक संरचना और मूल्य-व्यवस्था भी बदलती है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि नगरीकरण का प्रभाव नगर की सीमा पर रुकता नहीं। भारत सरकार (2025) की आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत की नगरीय-ग्रामीण सीमा तेज़ी से धुँधली हो रही है और अनेक ग्रामीण बस्तियाँ नगरीय विशेषताएँ धारण कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र (2019) के प्रक्षेपण भी संकेत देते हैं कि आने वाले दशकों में भारत की नगरीय जनसंख्या का हिस्सा निरंतर बढ़ेगा। इस प्रक्रिया का एक प्रमुख वाहक ग्राम-से-नगर पलायन है; ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन (2023) के अनुसार पलायन नगरीय वृद्धि के चार प्रमुख कारकों में से एक है, जो साथ-साथ भेजी गई विप्रेषण राशि के ज़रिये गाँव की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है।

गोरखपुर जिला इस विश्लेषण के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। भारत के महापंजीयक कार्यालय (2011) के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 44,40,895 है, जिसमें 81.17 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। एक ओर विशाल ग्रामीण आधार, दूसरी ओर तेज़ी से फैलता नगरीय केंद्र, यह द्वैत जिले को नगरीकरण-जनित ग्रामीण परिवर्तन के अध्ययन के लिए आदर्श बनाता है। प्रश्न यह है कि जब नगर का प्रभाव-क्षेत्र गाँवों तक फैलता है, तो ग्रामीण समाज की जाति-संरचना, संयुक्त परिवार, कृषि-निर्भरता और उपभोग-व्यवहार पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यही जिज्ञासा प्रस्तुत शोध का केंद्र है, जिसमें उपलब्ध शासकीय एवं शैक्षिक आँकड़ों के आधार पर इन परिवर्तनों की दिशा एवं मात्रा को समझने का प्रयास किया गया है।

2. साहित्य समीक्षा

नगरीकरण और ग्रामीण परिवर्तन पर व्यापक शोध साहित्य उपलब्ध है, यद्यपि उसमें कुछ रिक्तियाँ भी हैं। भगत (2011) ने जनगणना 2011 के आधार पर स्पष्ट किया कि भारत का नगरीकरण मुख्यतः लघु एवं मध्यम नगरों तथा नए "जनगणना नगरों" के उभार से संचालित है, न कि केवल महानगरों से। आर. सरकार (2019) ने आर्थिक सुधारों के पूर्व एवं पश्चात की तुलना करते हुए पाया कि जहाँ नगरीकरण की गति बढ़नी चाहिए थी वहाँ वह अपेक्षाकृत मंद रही, और यह असमानता नीतिगत ध्यान की माँग करती है। मोहन (2025) ने भी हाल में तर्क दिया कि भारत का नगरीकरण अपेक्षा से धीमा पड़ रहा है। रोज़गार-संक्रमण के आयाम पर चोइठानी, वैन डुइन एवं निजमैन (2021) का कार्य विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने पश्चिम बंगाल एवं बिहार के दो स्थलों पर प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा दिखाया कि 80 प्रतिशत से अधिक श्रमबल कृषि से हटकर गैर-कृषि कार्यों में जा चुका है, फिर भी ये बस्तियाँ आधिकारिक रूप से "नगर" नहीं मानी जातीं। निजमैन, वैन डुइन एवं चोइठानी (2026) इसी विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए इसे "स्थान में नगरीकरण" कहते हैं, जिसमें गाँव अपनी भौगोलिक जड़ पर रहते हुए भी सामाजिक-आर्थिक रूप से नगरीय बन जाता है। अब्राहम (2023) ने रेखांकित किया कि ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र में संक्रमण धीमा एवं असमान है, तथा निर्माण क्षेत्र इसका सबसे बड़ा अवशोषक है।

हिंदी शोध साहित्य भी इस दिशा में समृद्ध हो रहा है। राय (2021) ने ग्रामीण एवं नगरीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर का विश्लेषण करते हुए कृषि-संकट और पलायन को परिवर्तन का मूल कारक बताया। कुमारी एवं गुलिया (2026) ने हरियाणा के संदर्भ में ग्रामीण-से-नगरीय प्रवासन एवं सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण का ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया। प्रिया (2025) ने साहित्य-सिनेमा के माध्यम से दर्शाया कि औद्योगीकरण एवं नगरीकरण ने ग्रामीण पारंपरिक संरचनाओं को किस प्रकार विघटित किया। इग्नाइटेड माइंड्स (n.d.) में प्रकाशित विश्लेषण नगरीकरण की प्रवृत्ति, प्रभाव एवं समस्याओं को समेटता है, जबकि दृष्टि आई.ए.एस. (n.d.) इससे उपजते संसाधन-दबाव को रेखांकित करता है। कुल मिलाकर साहित्य दो बातों पर सहमत है, नगरीकरण ग्रामीण अर्थतंत्र को विविधता देता है, किंतु साथ ही असमानता एवं संसाधन-दबाव भी बढ़ाता है। तथापि जिला-स्तरीय, विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पर, केंद्रित विश्लेषण अपेक्षाकृत कम है, यही रिक्ति प्रस्तुत अध्ययन भरना चाहता है।

3. उद्देश्य

- गोरखपुर जिले में नगरीकरण की प्रवृत्ति तथा ग्रामीण-नगरीय जनसांख्यिकीय संरचना में हो रहे परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
- नगरीकरण से उत्पन्न ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों (कृषि से गैर-कृषि संक्रमण, साक्षरता, पलायन) का मूल्यांकन करना।

4. परिकल्पना

H_1: नगरीकरण की प्रक्रिया के साथ ग्रामीण जनसंख्या का सापेक्ष अनुपात घट रहा है तथा नगरीय हिस्सा बढ़ रहा है।

H_2: नगरीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भरता घटाकर गैर-कृषि रोज़गार, साक्षरता एवं पलायन को बढ़ाता है।

5. शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक अभिकल्प पर आधारित है। चूँकि उद्देश्य नगरीकरण-जनित परिवर्तनों की दिशा एवं मात्रा को प्रामाणिक आँकड़ों से समझना है, इसलिए अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर टिका है, न कि किसी काल्पनिक क्षेत्र-सर्वेक्षण पर।

अध्ययन क्षेत्र गोरखपुर जिला (उत्तर प्रदेश) है, जिसका चयन उसके विशाल ग्रामीण आधार तथा साथ-साथ तीव्र नगरीय विस्तार के द्वैत के कारण सोद्देश्य रूप से किया गया। आँकड़ों का प्रमुख स्रोत भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा प्रकाशित जनगणना 2011 (जिला जनगणना पुस्तिका, गोरखपुर) है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या प्रक्षेपण, वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा 2024-25, तथा विभिन्न शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित सत्यापित आँकड़ों का उपयोग किया गया, ताकि प्रवृत्ति 2025 तक विस्तारित की जा सके। विश्लेषण की इकाई जिला-स्तर है, जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय उप-समूहों की तुलना की गई।

विश्लेषण-तकनीक के अंतर्गत प्रतिशत, अनुपात, दशकीय वृद्धि-दर, तथा ग्रामीण-नगरीय तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया गया। जनसांख्यिकीय संकेतक (जनसंख्या, घनत्व), सामाजिक संकेतक (साक्षरता, लिंगानुपात) एवं आर्थिक संकेतक (कृषि/गैर-कृषि श्रमबल, नगरीय-ग्रामीण वृद्धि विभेदक) को अलग-अलग तालिकाओं में संगठित कर व्याख्या की गई। परिकल्पनाओं का परीक्षण संकलित द्वितीयक प्रवृत्तियों की दिशा एवं परिमाण के आधार पर किया गया (तालिका 7)। यह स्पष्ट है कि औपचारिक सांख्यिकीय सार्थकता-परीक्षण (जैसे chi-square) के लिए प्राथमिक क्षेत्र-आँकड़े आवश्यक होते हैं; अतः यहाँ निष्कर्ष प्रामाणिक प्रवृत्ति-आधारित हैं। अध्ययन की एक सीमा यह भी है कि जनगणना 2021 स्थगित रहने के कारण नवीनतम बिंदु प्रक्षेपित आँकड़ों पर निर्भर हैं।

6. परिणाम

तालिका 1: गोरखपुर जिले की ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या संरचना, 2011

क्षेत्र	जनसंख्या	प्रतिशत	पुरुष	स्त्री
ग्रामीण	36,04,766	81.17%	18,38,726	17,66,040
नगरीय	8,36,129	18.83%	4,39,051	3,97,078
कुल	44,40,895	100%	22,77,777	21,63,118

स्रोत: जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक कार्यालय।

तालिका 1 दर्शाती है कि गोरखपुर की चार में से लगभग चार व्यक्ति ग्रामीण हैं, 81.17 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है, जबकि केवल 18.83 प्रतिशत नगरीय है। जिले का घनत्व 1,337 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। यह संरचना पुष्टि करती है कि जिला अब भी अनिवार्यतः ग्रामीण है; अतः किसी भी नगरीकरण-जनित परिवर्तन का प्रभाव विशाल ग्रामीण जनसमूह पर पड़ता है, जो अध्ययन की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।

तालिका 2: गोरखपुर जिला जनसंख्या—दशकीय वृद्धि एवं प्रक्षेपण

वर्ष	जनसंख्या	टिप्पणी
2011	44,40,895	जनगणना
2021	—	स्थगित (कोविड)
2025	~52,00,000	प्रक्षेपित
2026	53,70,196	प्रक्षेपित
2036	57,20,010	प्रक्षेपित

स्रोत: जनगणना 2011 एवं जनसंख्या प्रक्षेपण (censusdata.in; censusofindia.net)।

तालिका 2 के अनुसार 2001-2011 दशक में जिले की जनसंख्या वृद्धि-दर 17.81 प्रतिशत रही। प्रक्षेपण संकेत देते हैं कि 2025 तक जनसंख्या लगभग 52 लाख तथा 2036 तक 57.2 लाख पहुँचेगी, अर्थात 2011 की तुलना में लगभग 28.8 प्रतिशत की समग्र वृद्धि। यह निरंतर वृद्धि नगरीय केंद्र पर दबाव बढ़ाती है और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय प्रभाव-क्षेत्र में खींचती है, जिससे भूमि-उपयोग एवं रोज़गार-ढाँचे में परिवर्तन प्रेरित होता है।

तालिका 3: ग्रामीण बनाम नगरीय साक्षरता एवं लिंगानुपात (गोरखपुर, 2011)

संकेतक	ग्रामीण	नगरीय
साक्षरता दर	68.02%	82.39%
पुरुष साक्षरता	80.30%	—
स्त्री साक्षरता	55.35%	—
लिंगानुपात	960	904
बाल लिंगानुपात (0-6)	—	892

स्रोत: जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक कार्यालय।

तालिका 3 एक तीव्र ग्रामीण-नगरीय अंतराल उजागर करती है, नगरीय साक्षरता (82.39%) ग्रामीण (68.02%) से लगभग 14 प्रतिशत बिंदु अधिक है। रोचक यह है कि लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र (960) में नगरीय (904) से बेहतर है, जो पुरुष-प्रधान श्रम-पलायन नगर की ओर होने का संकेत देता है। यह विरोधाभास दिखाता है कि नगरीकरण शैक्षिक अवसर तो बढ़ाता है, किंतु जनसांख्यिकीय संतुलन पर मिश्रित प्रभाव डालता है।

तालिका 4: भारत में ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या/श्रमबल वितरण एवं नगरीय वृद्धि विभेदक (2001-2011)

संकेतक	मान
ग्रामीण जनसंख्या हिस्सा (2011)	68.8%
ग्रामीण श्रमबल हिस्सा (2011)	72.4%
नगरीय जनसंख्या वृद्धि (2001-11)	31.8%
ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (2001-11)	12.18%
नगरीय वृद्धि में पलायन/पुनर्वर्गीकरण का योगदान	50% से अधिक

स्रोत: जनगणना 2011; भगत (2011)।

तालिका 4 दर्शाती है कि 2001-2011 में नगरीय जनसंख्या 31.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो ग्रामीण वृद्धि (12.18%) से ढाई गुना अधिक है। इस नगरीय वृद्धि का आधे से अधिक भाग ग्रामीण-से-नगरीय पलायन तथा ग्रामीण बस्तियों के नगरीय में पुनर्वर्गीकरण से आया। यह प्रवृत्ति स्पष्ट करती है कि नगरीकरण ग्रामीण श्रमबल को खींच रहा है और ग्रामीण-नगरीय सीमा को गतिशील बना रहा है।

तालिका 5: भारत में जनगणना नगरों (Census Towns) की वृद्धि

वर्ष	जनगणना नगरों की संख्या
1991	1,702
2001	1,362
2011	3,894

स्रोत: जनगणना 2011 (चोइठानी आदि, 2021 में उद्धृत)।

तालिका 5 "स्थान में नगरीकरण" का सशक्त प्रमाण है 2001 से 2011 के बीच जनगणना नगरों की संख्या 1,362 से बढ़कर 3,894 हो गई, अर्थात लगभग तीन गुना वृद्धि। ये वे पूर्व-ग्रामीण बस्तियाँ हैं जहाँ 75 प्रतिशत से अधिक पुरुष श्रमबल गैर-कृषि कार्यों में लग गया। यह आँकड़ा दिखाता है कि ग्रामीण क्षेत्र भौगोलिक रूप से गाँव रहते हुए भी आर्थिक-सामाजिक रूप से नगरीय बन रहे हैं।

तालिका 6: भारत में नगरीय जनसंख्या का दशकीय हिस्सा (%)

वर्ष	नगरीय जनसंख्या (%)
1981	23.34
1991	25.72
2001	27.81
2011	31.16

स्रोत: जनगणना, विभिन्न वर्ष; भगत (2011)।

तालिका 6 दीर्घकालीन प्रवृत्ति की पुष्टि करती है, भारत की नगरीय जनसंख्या का हिस्सा 1981 के 23.34 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 31.16 प्रतिशत हो गया, अर्थात तीन दशकों में लगभग 8 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि। यह निरंतर ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति H_1 को पुष्ट करती है कि नगरीय हिस्सा बढ़ने के साथ ग्रामीण सापेक्ष अनुपात घट रहा है, जिसका सीधा दबाव गोरखपुर जैसे ग्रामीण-बहुल जिलों पर पड़ता है।

तालिका 7: परिकल्पना परीक्षण सारांश

परिकल्पना	आधार (द्वितीयक साक्ष्य)	निर्णय
H_1	तालिका 2, 4, 6—नगरीय हिस्सा एवं वृद्धि-दर सतत बढ़ती	समर्थित
H_2	तालिका 3, 4, 5—गैर-कृषि संक्रमण, साक्षरता-अंतराल, पलायन	समर्थित

स्रोत: संकलित प्रवृत्ति-विश्लेषण, तालिका 1-6 पर आधारित।

तालिका 7 दोनों परिकल्पनाओं का प्रवृत्ति-आधारित आकलन प्रस्तुत करती है। तालिका 2, 4 एवं 6 की सुसंगत ऊर्ध्वगामी दिशा H_1 को समर्थित करती है। इसी प्रकार तालिका 3, 4 एवं 5 के साक्ष्य—बढ़ता गैर-कृषि श्रमबल, नगरीय साक्षरता-बढ़त एवं पलायन—H_2 को समर्थित करते हैं। निर्णय आँकड़ों की दिशा-परिमाण पर आधारित है; औपचारिक सार्थकता-परीक्षण हेतु प्राथमिक क्षेत्र-आँकड़े अपेक्षित रहेंगे।

7. विवेचना

परिणाम स्पष्ट रूप से दोनों उद्देश्यों की दिशा में संकेत करते हैं। पहले उद्देश्य जनसांख्यिकीय संरचना में परिवर्तन के संदर्भ में तालिका 1, 2 एवं 6 मिलकर एक सुसंगत चित्र बनाती हैं। गोरखपुर अब भी 81.17 प्रतिशत ग्रामीण है, किंतु जनसंख्या-प्रक्षेपण एवं राष्ट्रीय नगरीय-हिस्से की सतत वृद्धि यह दर्शाती है कि ग्रामीण सापेक्ष अनुपात धीरे-धीरे घट रहा है। यह प्रवृत्ति भगत (2011) के इस निष्कर्ष से मेल खाती है कि नगरीय वृद्धि अब ग्रामीण वृद्धि से आगे निकल गई है। तथापि यहाँ सावधानी आवश्यक है, आर. सरकार (2019) एवं मोहन (2025) चेतावनी देते हैं कि भारत का नगरीकरण अपेक्षा से मंद तथा असमान है। अतः गोरखपुर का परिवर्तन विस्फोटक नहीं, बल्कि क्रमिक एवं असमान है। दूसरा उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण, अधिक सूक्ष्म है। तालिका 4 एवं 5 का सम्मिलित पाठ बताता है कि परिवर्तन का मूल इंजन रोज़गार-ढाँचे में कृषि से गैर-कृषि की ओर संक्रमण है। चोइठानी, वैन डुइन एवं निजमैन (2021) तथा निजमैन, वैन डुइन एवं चोइठानी (2026) का कार्य इसे "स्थान में नगरीकरण" कहता है—गाँव अपनी भौगोलिक स्थिति पर रहते हुए भी आर्थिक रूप से नगरीय बन जाता है, जहाँ अधिकांश श्रमबल निर्माण, सेवा एवं लघु-व्यापार में चला जाता है। अब्राहम (2023) इसमें एक महत्त्वपूर्ण योग्यता जोड़ते हैं—यह संक्रमण अक्सर "स्थानांतरण" कम और "विविधीकरण" अधिक है, अर्थात परिवार पूर्णतः कृषि छोड़ने के बजाय आय-स्रोतों में विविधता लाते हैं, और निर्माण क्षेत्र इसका सबसे बड़ा अवशोषक है।

इस आर्थिक बदलाव के सामाजिक परिणाम गहरे हैं। तालिका 3 का साक्षरता-अंतराल दर्शाता है कि नगरीय संपर्क शैक्षिक आकांक्षा बढ़ाता है, किंतु लाभ असमान रूप से वितरित है। राय (2021) एवं प्रिया (2025) रेखांकित करती हैं कि नगरीय प्रभाव पारंपरिक संयुक्त परिवार, जाति-आधारित व्यवसाय एवं जीवनशैली को शिथिल करता है। पलायन इस प्रक्रिया की धुरी है—ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन (2023) तथा

कुमारी एवं गुलिया (2026) दिखाती हैं कि पलायन जहाँ कृषि पर श्रम-भार घटाता एवं विप्रेषण लाता है, वहीं यह गाँव में स्त्रियों, वृद्धों एवं बच्चों पर उत्तरदायित्व का असंतुलन भी बढ़ाता है। तालिका 3 में ग्रामीण लिंगानुपात का अपेक्षाकृत बेहतर होना इसी पुरुष-प्रधान पलायन का अप्रत्यक्ष संकेत है। फिर भी चित्र एकतरफ़ा नहीं। एक ओर नगरीकरण आय-विविधता, शिक्षा एवं गतिशीलता के अवसर देता है; दूसरी ओर यह कृषि-श्रम की कमी, भूमि पर सट्टेबाज़ी, अनौपचारिक-असुरक्षित रोज़गार एवं संसाधन-दबाव को जन्म देता है, जैसा इग्नाइटेड माइंड्स (n.d.) एवं दृष्टि आई.ए.एस. (n.d.) रेखांकित करते हैं। भारत सरकार (2025) की आर्थिक समीक्षा की चेतावनी प्रासंगिक है कि अनियोजित नगरीकरण नागरिक सुविधाओं पर भारी दबाव डालता है। अतः गोरखपुर के संदर्भ में उपयुक्त नीति वह है जो ग्रामीण गैर-कृषि रोज़गार को औपचारिक एवं सुरक्षित बनाए, कौशल-विकास को गाँव तक ले जाए, और नगर-ग्राम को प्रतिस्पर्धी नहीं, पूरक इकाइयों के रूप में विकसित करे।

8. निष्कर्ष

प्रस्तुत विश्लेषण से स्पष्ट है कि गोरखपुर जिले में नगरीकरण एक क्रमिक किंतु निर्णायक शक्ति के रूप में ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक बुनावट को नया आकार दे रहा है। यद्यपि जिला अब भी अत्यधिक ग्रामीण है, फिर भी नगरीय हिस्से की सतत वृद्धि, कृषि से गैर-कृषि रोज़गार की ओर संक्रमण, बढ़ता ग्राम-नगर पलायन तथा ग्रामीण-नगरीय साक्षरता-अंतराल सभी संकेतक दोनों परिकल्पनाओं को समर्थित करते हैं। नगरीकरण अवसर एवं असमानता दोनों साथ लाता है; यह आय-विविधता एवं शिक्षा को बढ़ाता है, किंतु कृषि-संकट, अनौपचारिक रोज़गार एवं सामाजिक असंतुलन को भी जन्म देता है। अतः आवश्यकता संतुलित एवं समावेशी ग्राम-नगर नियोजन की है, जिसमें ग्रामीण गैर-कृषि रोज़गार को सुरक्षित बनाया जाए तथा नगर-ग्राम को पूरक विकास-इकाइयों के रूप में देखा जाए। भावी शोध के लिए जिला-स्तरीय प्राथमिक क्षेत्र-सर्वेक्षण द्वारा इन प्रवृत्तियों की सांख्यिकीय पुष्टि उपयोगी सिद्ध होगी।

References

[1]. Aruchunan, M., Nivethitha, L., & Gowthami, R. (2023). A review of yoga on inflammation and its related diseases. *Annals of Rheumatology and Autoimmunity*, *3*(1), 1. https://doi.org/10.4103/ara.ara_16_22

[2]. अब्राहम, वी. (2023). भारत में ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र रोज़गार का मंद उदय: स्थानांतरण या विविधीकरण? *द इंडियन जर्नल ऑफ़ लेबर इकोनॉमिक्स, 66*(3). https://doi.org/10.1007/s41027-023-00452-7

[3]. भगत, आर. बी. (2011). भारत में नगरीकरण का उभरता स्वरूप (*Emerging pattern of urbanisation in India*). *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 46*(34), 10–12. https://www.epw.in/journal/2011/34/commentary/emerging-pattern-urbanisation-india.html

[4]. चोइठानी, सी., वैन डुइन, आर. जे., एवं निजमैन, जे. (2021). भारत के ग्रामीण-नगरीय संक्रमण पर बदलती आजीविकाएँ. *वर्ल्ड डेवलपमेंट, 146*, 105617. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105617

[5]. दृष्टि आई.ए.एस. (न.द.). *शहरीकरण से उपजते संकट*. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/crisis-of-urbanization

[6]. इग्नाइटेड माइंड्स जर्नल्स. (न.द.). *भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति, प्रभाव एवं समस्याऐं*. http://ignited.in/p/303449

[7]. कुमारी, स., एवं गुलिया, आर. एस. (2026). ग्रामीण हरियाणा से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन: एक ऐतिहासिक अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एडवांस्ड रिसर्च एंड मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रेंड्स (IJARMT), 3*(2). https://ijarmt.com/index.php/j/article/view/1042

[8]. भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय. (2011). *जिला जनगणना पुस्तिका: गोरखपुर, उत्तर प्रदेश (जनगणना 2011)*. https://www.census2011.co.in/census/district/559-gorakhpur.html

[9]. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय. (2025). *आर्थिक समीक्षा 2024-25, अध्याय 15: नगरीकरण*. https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap15.pdf

[10]. मोहन, आर. (2025). *भारत का नगरीकरण मंद पड़ रहा है: इस पर क्या किया जाए?* (*Indian urbanisation is slowing down*) (सी.एस.ई.पी. कार्य-पत्र 86). सेंटर फ़ॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. https://csep.org

[11]. निजमैन, जे., वैन डुइन, आर. जे., एवं चोइठानी, सी. (2026). ग्रामीण भारत में नगरीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन (*Urbanization and social change in rural India*). *अर्बन स्टडीज़*. https://doi.org/10.1177/00420980251364677

[12]. ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन. (2023). *भारत के शहरी विकास की कहानी में 'पलायन' की भूमिका*. https://www.orfonline.org/hindi/expert-speak/the-role-of-migration-in-india-s-urban-growth-story

[13]. प्रिया. (2025). लोक जीवन शैली पर आधुनिकता का प्रभाव (साहित्य और सिनेमा के संदर्भ में एक अध्ययन). *सहचर ई-पत्रिका* (ISSN: 2395-2873). https://www.sahchar.com/

[14]. राय, अ. (2021). भारत के ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों के सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एप्लाइड रिसर्च, 7*(6), 421–424. https://www.allresearchjournal.com/archives/2021/vol7issue6/PartF/9-3-54-841.pdf

[15]. सरकार, आर. (2019). आर्थिक सुधारों से पूर्व एवं पश्चात भारत में नगरीकरण: जनगणना आँकड़े क्या दर्शाते हैं?. *जर्नल ऑफ़ एशियन एंड अफ़्रीकन स्टडीज़, 54*(8). https://doi.org/10.1177/0021909619865581

[16]. संयुक्त राष्ट्र, आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग. (2019). *विश्व नगरीकरण संभावनाएँ: 2018 संशोधन*. संयुक्त राष्ट्र. https://population.un.org/wup/

Cite this Article:

***अवनीश कुमार एवं डॉ० हरिओम गुप्ता,"ग्रामीण पर्यावरण में नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण"**, *Ved International Journal of Arts, Commerce and Technology (VIJACT), ISSN: 3139-1656 (Online), Volume 2, Issue 2, pp. 58-64, February 2026.*

Journal URL: https://vijact.com

***DOI:** https://doi.org/10.65785/vijact.v2i2.18*